

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 96/XVIII(3)/2016-20(01)/2014—चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;
- (ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;
- (ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;
- (घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;
- (ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;
- (च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती;
- (छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
- (ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधानसभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशित;
- (झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और
- (ञ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गब्यालि,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014—WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2. The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee :

- (a) a representative of women residing in the affected area;
- (b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;

- (c) a representative of a voluntary organization working in the area;
- (d) a representative of a nationalized bank;
- (e) the Land Acquisition Officer of the project;
- (f) the Chairpersons of the panchayats or municipalities located in the affected area or their nominees;
- (g) the Chairperson of the District Planning Committee or his nominee;
- (h) the Member of Parliament and member of the Legislative Assembly of the concerned area or their nominees;
- (i) a representative of the Requiring Body; and
- (j) a administrator for Rehabilitation and Resettlement as the Member-Convenor.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 27-02-2016, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 15 राजस्व/147-14-03-2016-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।